

प्रेषक,

डा० रणवीर सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

वित्त नियंत्रक,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग:

देहरादून: दिनांक: 31 मार्च, 2008

विषय: अन्नपूर्णा योजना के क्रिय्यावयन हेतु वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्रांक-601/आ०ले०शा०/बजट-अन्नपूर्णा/2007 दिनांक- 04 दिसम्बर, 2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पोषित अन्नपूर्णा योजना हेतु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एन०एस०ए०पी० के अन्तर्गत आवंटित धनराशि में से अन्नपूर्णा योजना हेतु रू० 50.00 (रुपये पचास लाख मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में व्यय हेतु आपके निर्वहन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- 2- योजना के सुचारु संचालन/कार्यान्वयन हेतु शासनादेश संख्या: 440/खाद्य/अन्नपूर्णा योजना/2001, दिनांक: 04 अक्टूबर, 2001 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 3- आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अन्नपूर्णा योजना के जनपदवार संशोधित लाभार्थियों की सूचना वित्त नियंत्रक को उपलब्ध करायेंगे जिसके आधार पर जनपदवार आवंटन किया जायेगा तथा योजना के सम्बन्ध में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 4- स्वीकृत की जा रही धनराशि को व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त-पुस्तिका, मितव्ययता के विषय में शासन के आदेश, स्टोर पर्चेज रूल्स, टैण्डर विषयक नियमों का अनुपालन किया जायेगा।
- 5- व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किसी अन्य योजना पर धनराशि का व्यय कदापि नहीं किया जायेगा।
- 6- आगामी किस्त का प्रस्ताव भेजे जाने से पूर्व इस धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं भारत सरकार से प्रतिपूर्ति की गयी धनराशि का भी विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। राज्य से उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र न प्रस्तुत करने का समस्त दायित्व वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं जनपद स्तर पर जिला पूर्ति अधिकारी का ही माना जायेगा।

